



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2012/फाल्गुन 22, 1933

No. 104]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2012/PHALGUNA 22, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

सं. 3/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 138(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 को आगे संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (द्वितीय संशोधन) रूल्स, 2012 कहा जायेगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2 सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में, नियम 12कक के स्थान पर, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

“12कक कतिपय प्रकार के मामलों में प्रतिबंध लगाने की शक्ति- इन नियमों में निहित किसी बात के बावजूद, जहां कि केन्द्र सरकार, सेनवेट क्रेडिट के दुरुपयोग की सीमा तक, या इसकी प्रकृति और प्रकार और अन्य कारण जो सुसंगत हो, के बारे में इसकी यह राय है कि इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेनवेट क्रेडिट के प्रावधानों को रोकने के लिये, सार्वजनिक हित में कतिपय उपाय, जिनमें किसी विनिर्माता, प्रथम चरण या दूसरे चरण के डीलर या किसी निर्यातकर्ता पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल करना जरूरी है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके इन प्रतिबंधों को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिनमें

सेनवेट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना किसी डीलर के मामले में पंजीकरण को निलम्बन करना, उन सुविधाओं का प्रकार जिनको वापस लिया जाना है तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अदेश जारी किये जाने की प्रक्रिया भी शामिल है।

[फा. सं. 267/77/2011-के.उ.शु. 8]

बी. पी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण — मूल नियम अधिसूचना सं. 23/2004-के.उ.शु. (गै.टै.) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किये गये थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 01/2012-के.उ.शु. (गै.टै.) सा.का.नि. 83(अ) दिनांक 9 फरवरी, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012

No. 3/2012-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 138(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, for rule 12AA the following rule shall be substituted, namely:-

"12AAA: Power to impose restrictions in certain types of cases - Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of misuse of CENVAT credit, nature and type of such misuse and such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent the misuse of the provisions of CENVAT credit as specified in these rules, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter, may by a notification in the Official Gazette, specify the nature of restrictions including restrictions on utilization of CENVAT credit and suspension of registration in case of a dealer and type of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by an officer authorized by the Board".

[F. No. 267/77/2011-CX. 8]

V. P. SINGH, Under Secy.

Note.— The principal rules were published vide notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R.600 (E), dated the 10th September, 2004 and were last amended vide notification number 01/2012-Central Excise (NT); published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (I), vide number G.S.R 83(E), dated 9th February, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

सं. 4/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 139(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 को आगे संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जायेगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में नियम 12गग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित जायेगा, यथा:-

“12गगग कतिपय प्रकार के मामलों में प्रतिबंध लगाने की शक्ति- इन नियमों में किसी बात के निहित होते हुए भी, जहां केन्द्र सरकार, शुल्क अपवंचन, अपराधों की प्रकृति और प्रकार अथवा ऐसे अन्य करण, जो कि संगत हो, के संबंध में, की राय है, कि उत्पाद शुल्क की वंचन तथा इसके भुगतान में चूक को रोकने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी विनिर्माता, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबंधों सहित कुछ उपायों का प्रावधान करना जनहित में आवश्यक है, डीलर के मामले में पंजीकरण के निलम्बन, वापस ली जाने वाली सुविधाओं के प्रकार सहित प्रतिबंधों की प्रकृति बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश को जारी करने की प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया को, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

[फा. सं. 267/77/2011-के.उ.शु. 8]

वी. पी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं.04/2002-के.उ.शु. (गै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 2002 सा.का. नि.143 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किये गये थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2011-के.उ.शु. (गै.टै.), सा.का.नि. 971(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012

No. 4/2012-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 139(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:-

1.(1) These rules may be called the Central Excise (First Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 2002, for rule 12CC, the following rule shall be substituted, namely:-

"12CCC: Power to impose restrictions in certain types of cases.- Notwithstanding anything contained in these rules, where the Central Government, having regard to the extent of evasion of duty, nature and type of offences or such other factors as may be relevant, is of the opinion that in order to prevent evasion of, and default in payment of, duty of excise, it is necessary in the public interest to provide for certain measures including restrictions on a manufacturer, first stage and second stage dealer or an exporter, may by a notification in the Official Gazette, specify the nature of restrictions including suspension of registration in case of a dealer, types of facilities to be withdrawn and procedure for issue of such order by an officer authorized by the Board".

[F.No. 267/77/2011-CX. 8]

V. P. SINGH, Under Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 04/2002-CE(NT), dated the 1st March, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 143(E), dated the 1st March 2002 and were last amended vide notification number 32/2011-CE (NT), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1), vide number G.S.R 917(E), dated 30th December, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

सं. 5/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 140(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12गगग और सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 32/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 दिसम्बर, 2006, जिसे सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा, घोषित करती है कि जहां कहीं भी कोई विनिर्माता, प्रथम चरण या दूसरे चरण का डीलर या कोई निर्यातकर्ता, जिसमें व्यापारी निर्यातकर्ता भी शामिल है, प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि वह निम्न में से किसी भी कार्य में शामिल है :-

- (क) बीजक के दायरे में आये बिना या बिना शुल्क के भुगतान के माल को हटाना;
- (ख) शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ सही मूल्य की घोषणा किये बिना माल को हटा ले जाना जहां कि बिक्री मूल्य का एक हिस्सा, बीजक मूल्य से जितना अधिक है, वह प्राप्त कर लेता है या उसकी ओर से प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उसे बही-खाते में दर्ज नहीं किया जाता है;
- (ग) ऐसे दस्तावेज में विनिर्दिष्ट माल की रसीद के बिना सेनवेट क्रेडिट का लेना जिसके आधार पर उक्त क्रेडिट ली गई है;
- (घ) ऐसे बीजक या अन्य दस्तावेज पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना जिसके बारे में किसी भी व्यक्ति के लिए यह जानने का कारण है कि यह सही नहीं है;
- (ङ.) उक्त बीजक में विनिर्दिष्ट माल की डिलीवरी के बिना उत्पाद शुल्क के बीजक का जारी करना;
- (च) ऐसे बीजक या अन्य दस्तावेज पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क के आधार पर धन वापसी या छूट का दावा करना;
- (छ) ऐसे आदानों को हटाना जिस पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है, ऐसा सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, के नियम 3 के उपनियम (5) के अनुसार ऐसे आदानों पर प्राप्त किये गये क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान किये बिना करना।

तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिसूचना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट, सुविधाओं को वापस ले सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है।

2. वापस ली जाने वाली सुविधायें तथा लगाये जाने वाले प्रतिबंध:- (1) जहां कि कोई विनिर्माता प्रथम दृष्टया, पैरा-1 में विनिर्दिष्ट अपराधों को जानबूझ कर करने में संलग्न पाया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इन सुविधाओं पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है, यथा:-

- (i) निर्धारिती से शुल्क का भुगतान मासिक किये जाने की सुविधा को वापस लिया जा सकता है और तब उसके लिये यह जरूरी हो जायेगा कि वह प्रत्येक खेप के लिये उत्पादन शुल्क का भुगतान माल को हटाते समय करे।
- (ii) सेनवेट क्रेडिट के उपयोग के द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से रोका जा सकता है और तब निर्धारिती के लिये यह जरूरी हो जायेगा कि वह सेनवेट क्रेडिट के उपयोग के बिना ही उत्पाद शुल्क का भुगतान करे।

783 GI/12-2

(iii) निर्धारिती के लिये यह जरूरी किया जा सकता है कि वह उन प्रधान आदानों की भी प्राप्ति, निपटान, उपभोग और बीजक का हिसाब-किताब रखे जिसपर सेनवेट क्रेडिट नहीं प्राप्त किया गया है।

(iv) निर्धारिती के लिये यह जरूरी किया जा सकता है कि वह कारखाने में प्रधान आदान जिसपर चाहे सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं, की प्राप्ति के बारे में अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को, इस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, संसूचित करें और उक्त आदान को इस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाय।

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी या एक से अधिक प्रकार के अपराधों को जानबूझ कर करने में दूसरीबार या तदन्तर भी संलग्न पाया जाता है, उसके कारखाने से माल की प्रत्येक निकासी के लिए आदेश दिया जा सकता है कि यह बीजक के अंतर्गत किया जाय और जिसपर निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उक्त माल को कारखाने या भंडागार से हटाये जाने के पहले प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी होगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ पैरा 4 के उप-पैरा (3) के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है, सेनवेट क्रेडिट लेता रह सकता है, हालांकि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान के लिए उक्त क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा।

(ii) यदि निर्धारिती पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को दूसरी बार या तदन्तर करता है, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपवाक्य (I) और (II) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगा सकता है।

(iii) 'प्रधान आदान' से अभिप्राय ऐसे किसी भी आदान से है जिसका प्रयोग अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में होता है जहां ऐसे आदानों की लागत किसी दिये गये अंतिम उत्पाद की ईकाई मात्रा के विनिर्माण में प्रयुक्त कुल कच्चे माल की लागत के 10% से कम नहीं है।

(2) जहां पहले चरण अथवा दूसरे चरण का डीलर पैरा 1 की धारा (घ) अथवा (ड.) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध को जानबूझकर करने में शामिल पाया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

(3) निलम्बन की अवधि के दौरान उक्त डीलर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीजक जारी नहीं करेगा।

किन्तु, वह अपना व्यापार जारी रख सकता है और बीजक में व्यापार जारी रख सकता है और बीजक में उत्पाद शुल्क प्रदर्शित किए बिना बिक्री बीजक जारी कर सकता है और ऐसी बीजक के अंतर्गत वस्तुओं के प्राप्तकर्ता को कोई सेनवेट क्रेडिट देय नहीं होगा।

(4) जहां कोई निर्यातक व्यापारी जानबूझकर पैरा 1 के उपवाक्य (च) में विनिर्दिष्ट प्रकार का अपराध करने का दोषी पाया जाता है, वहां स्वतः सील करने की सुविधा वापस ली जा सकती है, जिसके बाद प्रत्येक निर्यात प्रेषण वहां के क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच तथा सील किया जाएगा:

(5) यदि कोई विनिर्माता, प्रथम चरण या दूसरे चरण का डीलर या कोई निर्यातकर्ता पैरा (1) के उपवाक्य (च) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उनको प्राप्त अन्य सुविधाओं को भी वापस ले सकता है।

(3) आर्थिक सीमा:- इस अधिसूचना से संबंधित प्रावधान उन स्थितियों में ही लागू होंगे, जहां पैरा 1 में विनिर्दिष्ट अपराधों के संदर्भ में आरोपित शुल्क या सेनवेट क्रेडिट 10 लाख रुपये से अधिक है।।

4. प्रक्रिया:- (1) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अपर महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, जैसा लागू हो दस्तावेज तथा अन्य प्रमाणों के जांच के बाद और अपने आपको संतुष्ट करने के बाद कि उस व्यक्ति ने जान बूझकर पैरा 1 में वर्णित अपराध किया है, एक प्रस्ताव, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना जैसा लागू हो, को वापस ली जाने वाली सुविधाओं तथा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की सूची उनकी समय सीमाओं के साथ जिस दौरान ये वापस लिये जाएंगे या प्रतिबंधित किए जायेंगे जहां तक संभव हो, मामले में, पता चलने के तीस दिनों के भीतर भेजेगा।

(2) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, जैसा लागू हो, प्राप्ति की जांच करेगा तथा प्रस्ताव के साथ प्राप्त दस्तावेज तथा प्रमाणों से अपने आपको संतुष्ट करने के बाद यदि पाता है कि वे प्रथम दृष्टया यह उचित विश्वास करने योग्य है, कि उस व्यक्ति ने जान बूझकर पैरा 1 में वर्णित अपराध किया है, उस प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं के साथ बोर्ड को भेज सकता है।

783 GI/12-3

बशर्ते कि मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की जा रही है, को अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर देगा और उस पर विचार करने के बाद ही वह अपनी अनुशंसा बोर्ड में भेजेगा।

(3) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना से प्राप्त अनुशासकों की जांच करेगा और वापस ली जाने वाली सुविधाओं और लगाए जाने वाले प्रतिबंधों संबंधी-उन समय सीमाओं के साथ जिसमें ये सुविधायें नहीं दी जायेंगी या जिस दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे- को विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

[फा. सं. 267/77/2011-के.उ.शु. 8]

वी. पी. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012

No. 5/2012-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 140(E).— In pursuance of rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002, and rule 12AAA of the CENVAT Credit Rules, 2004 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 32/2006-Central Excise (N.T.), dated the 30th December, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide G.S.R number 782 (E) dated the 30th December, 2006, the Central Government, hereby declares that where a manufacturer, first stage or second stage dealer, or an exporter including a merchant exporter is prima facie found to be knowingly involved in any of the following,-

- (a) removal of goods without the cover of an invoice and without payment of duty;
- (b) removal of goods without declaring the correct value for payment of duty, where a portion of sale price, in excess of invoice price, is received by him or on his behalf but not accounted for in the books of account;
- (c) taking of CENVAT Credit without the receipt of goods specified in the document based on which the said credit has been taken;
- (d) taking of CENVAT Credit on invoices or other documents which a person has reasons to believe as not genuine;
- (e) issuing duty of excise invoice without delivery of goods specified in the said invoice;
- (f) claiming of refund or rebate based on the duty of excise paid invoice or other documents which a person has reason to believe as not genuine;

(g) removal of inputs as such on which Cenvat credit has been taken, without paying an amount equal to credit availed on such inputs in terms of sub-rule (5) of rule 3 of the Cenvat Credit Rules, 2004,

an officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may order for withdrawal of facilities or impose the restrictions as specified in para 2 of this notification.

2. Facilities to be withdrawn and imposition of restrictions.- (1) Where a manufacturer is prima facie found to be knowingly involved in committing the offences specified in para 1, the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may impose following restrictions on the facilities, namely:-

- (i) the monthly payment of duty of excise may be withdrawn and the assessee shall be required to pay duty of excise for each consignment at the time of removal of goods;
- (ii) payment of duty of excise by utilisation of CENVAT credit may be restricted and the assessee shall be required to pay duty of excise without utilising the CENVAT credit;
- (iii) the assessee may be required to maintain records of receipt, disposal, consumption and inventory of the principal inputs on which Cenvat credit has not been taken;
- (iv) the assessee may be required to intimate the Superintendent of Central Excise regarding receipt of principal inputs in the factory on which Cenvat credit has or has not been taken, within a period specified in the order and the said inputs shall be made available for verification upto the period specified in the order:

Provided that where a person is found to be knowingly involved in committing any one or more type of offences as specified in para 1 for the second time or subsequently, every removal of goods from his factory may be ordered to be under an invoice which shall be countersigned by the Inspector of Central Excise or the Superintendent of Central Excise before the said goods are removed from the factory or warehouse.

Explanation.- For the purposes of this paragraph, it is clarified that-

- (i) a person against whom the order under sub-para (3) of para 4 has been passed may continue to take CENVAT credit, however, he would not be able to utilize the credit for payment of duty during the period specified in the said order.
- (ii) if the assessee commits any offence specified in para 1 for the second time or subsequently, the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may impose the restriction specified in clauses (i) and (ii).
- (iii) "principal inputs", means any input which is used in the manufacture of final products where the cost of such input constitutes not less than 10% of the total cost of raw materials for the manufacture of unit quantity of a given final products.

(2) Where a first stage or second stage dealer is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified at clauses (d) or (e) of para 1, the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may order suspension for a specified period, the registration granted under rule 9 of the Central Excise Rules 2002.

(3) During the period of suspension, the said dealer shall not issue any Central Excise Invoice:

Provided that he may continue his business and issue sales invoices without showing duty of excise in the invoice and no CENVAT credit shall be admissible to the recipient of goods under such invoice.

(4) Where a merchant exporter is found to be knowingly involved in committing the type of offence specified in clause (f) of para 1, the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may order withdrawal of the self sealing facility for export consignment and each export consignment shall be examined and sealed by the jurisdictional Central Excise Officer:

(5) If a manufacturer, first stage dealer or second stage dealer or an exporter does anything specified in clause (f) of para 1, the officer authorized by the Central Board of Excise and Customs may order withdrawal of the other facility available to them.

3. Monetary limit.- The provisions of this notification shall be applicable only in a case where the duty of excise or CENVAT Credit alleged to be involved in anything specified in para 1 exceeds rupees ten lakhs.

4. Procedure.- (1) The Commissioner of Central Excise or Additional Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, after examination of records and other evidence, and after satisfying himself that the person has knowingly committed the offence as specified in para 1, may forward a proposal to the Chief Commissioner or Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, to withdraw the facilities and impose restriction during or for such period, within 30 days of the detection of the case, as far as possible.

(2) The Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence, as the case may be, shall examine the said proposal and after satisfying himself that the records and evidence relied upon in the said proposal are sufficient to form a reasonable belief that a person has knowingly done or contravened anything specified in para 1, may forward the proposal along with his recommendations to the Central Board of Excise and Customs:

provided that the Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence, before forwarding his recommendations, shall give an opportunity of being heard to the person against whom the proceedings have been initiated and shall take into account any representation made by such person before he forwards his recommendations to the Central Board of Excise and Customs.

(3) An officer authorized by the Central Board of Excise and Customs shall examine the recommendations received from the Chief Commissioner of Central Excise or Director General of Central Excise Intelligence and issue an order specifying the type of facilities to be withdrawn or type of restrictions imposed, along with the period for which said facilities will not be available or the period for which the restrictions shall be operative.

[F.No. 267/77/2011-CX. 8]

V.P. SINGH, Under Secy.